कोटा जिला–वर्तमान सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

राजस्थान सरकार के विकास और जन कल्याण के संकल्प को साकार कर आमजन को जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन देने के लिये जिला प्रशासन पूर्णरूप से कटिबद्व है। गांव और गरीब की झोपडी तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है वहीं जिले के विकास के बडे–बडे प्रोजेक्ट्स को गति प्रदान करने के लिये निरंतर समीक्षा की जा रही है। वर्तमान सरकार के समय में कोटा जिले की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार रही :–

नगरीय विकास :–

- नगर विकास न्यास द्वारा वर्ष 2009–2010 में कोटा शहर के विकास कार्यो पर 148.64 करोड रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2010–2011 के लिये 504.77 करोड रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- पेयजल व्यवस्था सुदृढीकरण के लिये 100 करोड रूपये की योजना बनाई गई है।
- वर्तमान में 181.51 करोड रूपये के 26 प्रमुख विकास कार्य हाथ में लिये गये है।
- यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत 42.05 करोड रूपये के सीवरेज के कार्य तथा चम्बल नदी सुदृढीकरण परियोजना के तहत 122.31 करोड रूपये के कार्यो के कार्यादेश जारी किये गये है।
- करणी नगर, लखावा, अनन्तपुरा एवं सुभाष नगर आवासीय योजनाओं में 168 आवासों का एवं 1027 भूखण्डों का आवंटन किया गया है। स्वीकृत कृषि भूमि योजनाओं में 1820 एवं कच्ची बस्तियों में 1634 पट्टे जारी किये गये है।

ग्रामीण विकास :–

- महानरेगा योजना में 219702 परिवारों के 276539 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर 98.51 लाख मानव श्रम दिवस सृजित किये गये। योजना के तहत 43236 परिवारों ने 100 दिवस रोजगार पूर्ण किया।
- स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन में जिला वर्ष 2009–2010 में राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। योजना में 315 लाख रूपये के विपरित 398.59 लाख रूपये का साख सृजन किया गया।
- ग्रामीण समस्याओं का ग्राम स्तर पर ही निस्तारण करने के लिये जिले में ग्राम पंचायत सचिवालय व्यवस्था सफलता पूर्वक लागू की गई।

जल सरंक्षण :–

- जल संरक्षण की दिशा में नदियों को सदानिरा बनाने की पहल के तहत 26 नये एनीकट बनाने, पूर्व के साथ एनीकटों की ऊंचाई बडा कर जल ग्रहण क्षमता में वृद्वि करने के लिये 38 करोड रूपये की कार्य योजना बनाकर क्रियान्विति प्रारम्भ कर दी गई है। योजना में 10 एनीकटों से पेयजल आपूर्ति करना भी शामिल किया गया है।
- कालीसिंध नदी पर बालाजी की थाक के समीप 2.19 करोड रूपये से हरिपुरा मांझी एनीकट एवं परवन नदी पर 5 करोड रूपये की जनभागीदारी से राजगढ एनीकट के निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गये है। विभागीय मद से खेडारसूलपुर एवं चन्द्रेसल एनीकट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
- किशनपुरा लघु सिंचाई लिफ्ट परियोजना का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है जिसपर अभी तक 400. 98 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

विघुत उत्पादन :–

- सरकार की 90 दिन की कार्ययोजना में शामिल कर कोटा सूपर थर्मल पावर स्टेशन की 195 मेघावाट क्षमता की 7 वीं ईकाई का निर्माण कार्य तेजी से पूरा कर विघुत उत्पादन शुरू किया गया।
- कोटा शहर की विघुत तंत्र में व्यापक सुधार लाने के लिये 252 करोड रूपये की एक्सीलेरेटेड पॉवर डवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम पार्ट–बी (एपीडीआरपी–बी) योजना प्रस्तावित है।
- गुणवत्ता युक्त विघुत आपूर्ति के लिये देवली एवं मायला कुदायला में 132 केवी ग्रीड सब स्टेशन का निर्माण पूर्ण कराया गया, मण्डाना में कार्य प्रगति पर चल रहा है तथा दीगोद सुल्तानपुर, बपावर व

कोटा के दादाबाडी में इतनी ही क्षमता के जीएसएस स्थापना के प्रस्ताव निगम मुख्यालय को भिजवाये गये है।

- निगम द्वारा 33 किमी लम्बी 33 केवी लाईन, 501 लम्बी 11 केवी लाईन बिछाई गई तथा 25 फीडर सुधार कार्य पूर्ण किये गये। निगम द्वारा 3293 कुओं का ऊर्जीकरण किया गया, कुटीर योजना में 2034 कनेक्शन तथा 330 औधोगिक व 11149 घरेलू कनेक्शन जारी किये गये।

स्वच्छ पेयजल :–

- रामगंजमण्डी–पंचपहाड जलप्रदाय योजना पूर्ण कर 142 गांवों एवं 3 नगरीय क्षेत्रों को पेयजल से लाभान्वित किया गया।
- 90 दिवस कार्य योजना में करीब 10 करोड रूपये से अधिक की विभिन्न जलप्रदाय योजनाऐं पूर्ण कर ग्राम वासियों को पेयजल उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण योजनाओं पर 777.32 लाख रूपये व्यय किये गये।
- जिले में 67 नलकूप, 562 हैण्डपम्प, 110 सिंगल फेज स्थापित कर चालू किये गये। जिले की शहरी योजनाओं पर 777.27 लाख रूपये व्यय किये गये। हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 13943 एवं शहरी क्षेत्रों में 1484 हैण्डपम्प दुरूस्त किये गये।

सडक निर्माण :–

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोटा बाईपास निर्माण का 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाकर यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राधिकरण द्वारा देवली–कोटा खण्ड को 4 लेन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में 15 कार्य पूर्ण कर 136.80 किमी सडक का निर्माण कर 35.05 करोड रूपये व्यय किये गये। केन्द्रीय सडक निधि योजना में 14.15 करोड रूपये व्यय कर 76.10 किमी सडक का निर्माण किया गया।
- सीसवाली–अन्ता–सांगोद सडक पर परवन नदी के ऊपर 19.10 करोड रूपये स्वीकृत किये जाकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। कोटा–इटावा मार्ग पर ढीपरी गांव से गणेशगंज तक 13 किमी सडक सुदृढीकरण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। महानरेगा योजना में 50.07 करोड रूपये के सडक निर्माण के 59 कार्य पूर्ण कर लिये गये है तथा 172 कार्य प्रगति पर है।

खुशहाल हो किसान :–

- कृषकों की कुशहाली के लिये सीएडी नहरी तंत्र में 27 वितरिकाओं के जीर्णोद्वार के लिये 45.60 करोड रूपये तथा विश्व बैंक के सहायोग से 104 करोड रूपये के सुदृढीकरण कार्य कराये जा रहे है। महानरेगा योजना के तहत नहर सुदृढीकरण के 12 करोड रूपये के कार्य कराये गये एवं 64 करोड रूपये के कार्य प्रगति पर चल रहे है।
- दांई एवं बाई मुख्य नहर के सुदृढीकरण हेतु क्रमशः 485.27 करोड एवं 474.30 करोड रूपये के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये है।
- सीएडी परियोजना क्षेत्र में कृषकों को ब्याज माफी की छूट से करीब 80 हजार कृषक लाभान्वित हुये और उनसे 557.61 लाख रूपये की सिंचाई कर की वसूली की गई।
- वर्ष 2009–10 में 8038.33 है0 क्षेत्र में भूमि सुधार कार्य कराये गये जिस पर 482.30 लाख रूपये व्यय किये गये। चालू वित्तीय वर्ष में 6000 है0 का लक्ष्य रखा गया जिसके विपरित अभी तक 4889 है0 में भूमि सुधार कार्य किया जा चुका है।
- कृषि विभाग द्वारा जिले की 156 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि ज्ञान एवं आदान शिविर, खरीफ अभियान संचालित कर समय पर कृषकों को कृषि आदान की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
- उघान विभाग द्वारा फलदार बगीचों की स्थापना, मधुमक्खी पालन, फसलोत्तर प्रबंधन व माईक्रोइरिगेशन को बढावा देने के लिये कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

- कृषि उपज मण्डी समिति में कृषकों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के आपणी रसोई योजना शुरू की गई। मण्डी समिति द्वारा 274.32 लाख रूपये व्यय कर 34 सम्पर्क सडकों का निर्माण कार्य कराया गया तथा वर्तमान में 852.56 लाख रूपये के कार्य प्रगति पर है।
- कृषि कार्य करते समय मृत्यु अथवा दुर्घटना होने पर राजीव गांधी कृषक साथी योजना में 47 काश्तकारों व खेतिहर श्रमिकों को 17.53 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध कराई गई।
- सहकारी बैंक द्वारा 141.49 करोड रूपये के ऋण किसानों को वितरित किये गये तथा 2406 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये।
- किसानों को कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, पम्पसेट, कुआ गहरा कराने, नया कुआ बनाने व डेयरी संचालन आदि कार्यो के लिये 772.84 लाख रूपये के दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराये गये।
- किसानो को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये 21.96 करोड रूपये की कृषि उपज का क्रय सहकारी संस्थाओं द्वारा किया गया।

<u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :–</u>

- सुरक्षित मातृत्व के तहत संस्थागत प्रसव को बढावा देते हुये 45561 संस्थागत प्रसव कराये गये तथा जननी सुरक्षा योजना में 29621 महिलाओं को 443.08 लाख रूपये की सहायता प्रदान की गई।
- मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना में 75986 बीपीएल रोगियों को 337.82 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध कराई गई।
- बपावर कलां, बालूहेडा, गेंता में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिये 28–28 लाख रूपये तथा कोल्ड चैन स्टोरेज के निर्माण के लिये 12.50 लाख रूपये स्वीकृत हुये। मण्डाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 31.25 लाख, सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 115 लाख, खेडा रसूलपुर व मण्डावरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 28–28 लाख, भीमगंजण्डी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 50 लाख, कैथून, इटावा, सुल्तानपुर व रामगंजमण्डी में जननी सुरक्षा योजना वार्ड निर्माण के लिये 19–19 लाख रूपये विविध स्वास्थ्य सुविधाऐं जुटाने के लिये राशि से निर्माण कार्य करावाये गये।

<u>महिला एवं बाल विकास :–</u>

- जिले में 1121 पूर्ण एवं 152 मिनी आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से 104500 बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में 84 आगंनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य भी कराये जा रहे है।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये 550 महिलाओं को विभिन्न व्यवसाओं में प्रशिक्षण दिया गया।
- जिले में 1800 महिला स्वंय सहायता समूह गठित कर 927 को बैंकों से 213.05 लाख रूपये के ऋण उपलब्ध कराये गये। सामूहिक विवाह अनुदान योजना में 147 जोडों को 8.82 लाख रूपये की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई।

<u>कमजोर वर्गो का उत्थान :–</u>

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पालनहार योजना में 1082 बालक बालिकाओं को 1.26 करोड रूपये, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 24 व्यक्तियों को अत्याचार निवारण के तहत 8.87 लाख रूपये, 27 निशक्तों को विवाह अनुदान योजना के तहत 6 लाख रूपये, 10 निशक्तों को विश्वास योजना में स्वरोजगार हेतु 1.30 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया। सहायोग योजना में 516 बीपीएल परिवार की व्यस्क पुत्रियों को विवाह हेतु 48.05 लाख रूपये की सहायता प्रदान की गई।
- विभाग द्वारा अध्यनरत् अनुसूचिज जाति, जनजाति एवं पिछडे वर्ग के 8284 छात्र–छात्राओं को 17.64 करोड रूपये की उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया।
- अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछडा वर्ग के लिये संचालित 17 छात्रावासों के माध्यम से 1393 बालक बालिकाओं को लाभान्वित कर 1.55 करोड रूपये व्यय किये गये। कोटा शहर में निराश्रित बालकों के

लिये 4 ईकाईयों के माध्यम से 170 बालक बालिकाओं को लाभान्वित कर 12.03 लाख रूपये व्यय किये गये। भिक्षावृत्ति एवं अवांछनीय प्रवृत्तियों में लिप्त परिवारों के लिये मण्डाना में संचालित आवासीय विघालय में 116 बच्चों को लाभान्वित कर 49.70 लाख रूपये व्यय किये गये।

<u>शिक्षा विकास :–</u>

- 90 दिन कार्य योजना में 7.30 करोड रूपये से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा कराया गया। इस विश्वविद्यालय में गत वर्ष कई विषयों पर पीएचडी पाठ्यक्रम तथा 9 विषयों में एम टेक पाठ्यक्रम शुरू किये गये। जेडीबी गर्ल्स कोलेज में विकास कार्यो पर 79.50 लाख रूपये व्यय किये गये तथा रसायन विभाग को यूजीसी द्वारा 35 लाख रूपये की परियोजना स्वीकृत की गई।
- माध्यमिक शिक्षा के तहत आपकी बेटी योजना में 139 बालिकाओं, ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना में 613 तथा साईकिल योजना में 254 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।
- प्रारम्भिक शिक्षा के तहत मां–बेटी योजना में 140, इन्सपायर एवार्ड योजना में 232, स्वास्थ्य मित्र योजना में 84 एवं विकंलाग शिक्षा योजना में 54 बच्चों को लाभान्वित किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विघालयों में निशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराई गई।
- मिड–डे–मील योजना में 1402 विधालयों के 1350884 छात्र छात्राओं को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम में 33670.35 क्वि. गेंहू/चावल का उपयोग किया गया तथा 668.53 लाख रूपये व्यय किये गये।
- नंदी फाउण्डेशन संस्था द्वारा संचालित केन्द्रीय रसोईघर के माध्यम से कोटा शहर व लाडपुरा ब्लॉक के 100 विघालयों में मिड–डे–मील के तहत पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

<u>हरित राजस्थान :–</u>

- हरित राजस्थान के तहत वन विभाग द्वारा 200 है0 में वृक्षारोपण कार्य कराया गया तथा 50 है0 में अग्रिम कार्य कराया गया।
- महानरेगा योजना से वन विभाग द्वारा 11 नर्सरियों का विकास किया गया। इन नर्सरियों में 23 लाख पौध तैयार करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा इस वर्ष नर्सरियों में करीब 4.50 लाख पौधे तैयार किये जा चुके है।
- महानरेगा योजना में वन विभाग द्वारा 151 कार्य पूर्ण करा लिये गये है जिनपर 334 लाख रूपये व्यय किये गये। ईको रेस्टोरेशन के तहत 25 किमी पक्की सुरक्षा दिवार बनाने के कार्य प्रगति पर चल रहे है।

<u>विविध :–</u>

- उधोग विभाग द्वारा विभिन्न उधोगों में 45.19 करोड रूपये की पूंजी का विनियोजन कर 4303 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- कोटा में वस्त्र उधोग को बढावा देने के लिये रेडिमेट गारमेंट जोन का विकास किया गया। इससे करीब 1000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।
- औधोगिक विकास में शिक्षा के क्षैत्र में विनियोजन को प्रोत्साहित करने के लिये 19.37 एकड भूमि में 6 भूखण्ड स्वीकृत किये गये जिनमें 66.68 करोड रूपये का निवेश संभावित है।
- खाद्व प्रदार्थो के मिलावट की रोकथाम के लिये चल प्रयोगशाला के माध्यम से 298 नमूनों की जांच की गई।
- उपभोक्ता सप्ताह के तहत जिले में 63900 बीपीएल परिवारों, 18298 अन्त्योदय परिवारों एवं 5721 अन्नपूर्णा परिवारों को उपभोक्ता वस्तुऐं उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा रहा है।
- पशुपालन विभाग द्वारा 1.30 लाख पशुओं की चिकित्सा, 1.38 लाख पशुओं का टिकाकरण, 19042 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान एवं 24409 पशुओं का बधियाकरण किया गया। पशु बीमा योजनाओं से 3541 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।